



# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 39 पटना, बुधवार, 6 आश्विन 1944 (श०)  
28 सितम्बर 2022 (ई०)

विषय-सूची		पृष्ठ
भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-6	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0ए0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	भाग-9—विज्ञापन
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4—बिहार अधिनियम	---	पूरक
		पूरक-क

7-7
8-14

# भाग-1

## नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

### ग्रामीण विकास विभाग

#### अधिसूचनाएं

8 सितम्बर 2022

सं0 ग्रा0वि0-R-503/79/2022-Section 14-RDD-RDD-1216804—श्री परमानन्द पंडित, प्रखंड विकास पदाधिकारी, फतेहपुर, गया के विरुद्ध उप विकास आयुक्त, गया के पत्रांक- 1155 दिनांक- 28.04.2022 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है। आरोप पत्र में श्री पंडित के विरुद्ध आवास प्लस अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में किये जा रहे पंजीकरण/जिओ टैगिंग/ ऑर्डरसीट जेनरेशन/एफ0टी0ओ0 का सत्यापन कार्य में लापरवाही एवं वरीय पदाधिकारी के द्वारा दिये गये आदेश की अवहेलना का आरोप अंकित किया गया है।

आरोप पत्र पर श्री पंडित से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सभी ग्रामीण आवास सहायकों को कई बैठकों, व्हाटसएप ग्रुप, पत्राचार एवं दूरभाष पर निदेश दिया गया किन्तु उनके द्वारा योग्य लाभुकों का आवेदन पत्र एवं जांच सूची उपलब्ध कराने में विलंब किया गया। फतेहपुर प्रखंड में 930 लाभुकों का पंजीकरण (रिमांड- 89, अस्थायी प्रवास- 391, जॉब कार्ड- 262, मृत्यु-13 एवं लक्ष्य वापसी- 175) लंबित है। अस्थायी प्रवासन के कारण 247 लाभुकों का निबंधन कार्य लंबित है। लंबित ऑर्डरसीट मात्र 393 है, जो 119 मिसमैच, 145 रिमांड, आधार मिसमैच के कारण 32 लंबित है। शेष 97 का ऑर्डरसीट शीघ्र बनाया जा रहा है।

उप विकास आयुक्त, गया से प्रतिवेदित आरोप एवं श्री पंडित के स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि गया जिला के 24 प्रखंडों में फतेहपुर प्रखंड की स्थिति नीचे से 5वें नम्बर पर अर्थात् उपर से प्रखंड की स्थिति 20वें पायदान पर थी। लंबित एफ0टी0ओ0 के मामले में फतेहपुर प्रखंड 24वें पायदान पर है। 27.07.2022 की उपलब्धि को देखने से स्पष्ट होता है कि कुल लक्ष्य 8768 के विरुद्ध केवल 279 आवास अर्थात् केवल 3.08 प्रतिशत पूर्ण कराया गया है, जो परिलक्षित करता है कि आवास निर्माण की प्रगति में प्रखंड की स्थिति अच्छी नहीं है। अतः श्री पंडित का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री परमानन्द पंडित, प्रखंड विकास पदाधिकारी, फतेहपुर, गया को लघुदंड के रूप में "असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि" अवरुद्ध करने का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री परमानन्द पंडित की चारित्रिकी में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
बालामुरुगन डी0, सचिव।

13 सितम्बर 2022

सं0 ग्रा0वि0- 14(पटना) नालंदा(लोक प्राधिकार)-06/2021-1232566—श्री पंकज कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, परवलपुर, नालंदा सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाराचट्टी (गया) के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-102 दिनांक-22.12.2020 के द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ। आरोप पत्र में श्री कुमार के विरुद्ध लोक प्राधिकार की सुनवाईयों में अनुपस्थित रहने से संबंधित आरोप अंकित किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर श्री पंकज कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री कुमार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दिनांक- 19.12.2020 को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, हिलसा के न्यायालय में परिवाद की सुनवाई निर्धारित थी। लेकिन कोरोना पॉजेटिव हो जाने के कारण चिकित्सक के द्वारा आराम करने का सलाह दी गयी थी। उक्त कारणवश दिनांक- 16.12.2020 से 21.12.2020 तक अवकाश पर रहने के कारण उक्त सुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थ था।

आरोप पत्र में गठित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि दिनांक- 19.12.2020 की सुनवाई में उपस्थित नहीं होने के संबंध में उनके द्वारा कोई ठोस आधार नहीं दिया गया है, ऐसी स्थिति में श्री कुमार का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री पंकज कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, परवलपुर, नालंदा सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाराचट्टी (गया) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010 के नियम-3 के तहत 'चेतावनी (पत्र निर्गत की तिथि से)' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री पंकज कुमार की चारित्रि पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

**आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।**

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
बालामुरुगन डी0, सचिव।

16 सितम्बर 2022

सं0 ग्रा0वि0-14(भा0) बाँका -03/2019-1240553—श्री अमित कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाँसी, बाँका सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर (सहरसा) के विरुद्ध प्रशिक्षु आई0ए0एस0, के प्रखंड प्रशिक्षण में योगदान हेतु प्रभार नहीं सौंपने, अनधिकृत रूप से विभिन्न दिवसों व महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने, स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं देने, योजनाओं के क्रियान्वयन में रुचि नहीं लेने, निर्वाचन कार्यों में लापरवाही इत्यादि के लिए जिला पदाधिकारी, बाँका के पत्रांक- 670 दिनांक- 30.11.2019 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ तथा जिला पदाधिकारी, बाँका के ज्ञापांक 97 दिनांक 18.01.2020 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उनकी लापरवाही एवं अनुपस्थित रहने आदि आरोप प्रतिवेदित किए गए। उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय अधिसूचना संख्या- 455663 दिनांक- 01.02.2020 द्वारा श्री कुमार को निलंबित किया गया एवं संकल्प संख्या- 461606 दिनांक- 04.05.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर श्री कुमार से लिखित अभ्यावेदन की माँग की गई। संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के अभिमत से सहमत होते हुए श्री कुमार के विरुद्ध पत्रांक- 471739 दिनांक-23.06.2021 द्वारा निलंबन मुक्त कर असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने का दंड अधिरोपित किया गया।

श्री अमित कुमार से प्राप्त निलंबन अवधि के वेतन एवं भत्ता के भुगतान तथा सेवा विनियमन से संबंधी अभ्यावेदन पर विचारोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया जाता है।

1. निलंबन की अवधि (दिनांक 01.02.2020 से दिनांक 23.06.2021) अन्य प्रयोजनों के लिए कर्तव्य पर

बितायी गई अवधि मानी जाएगी।

2. चूँकि श्री कुमार को असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने का दंड दिया गया है। अतः श्री कुमार को निलंबन अवधि का वेतन एवं अन्य भत्तों का 95 प्रतिशत राशि देय होगा।  
उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
बालामुरुगन डी0, सचिव।

**कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय  
गृह विभाग (कारा)**

**अधिसूचनाएं**

**21 सितम्बर 2022**

सं0 कारा/स्था0(अधी0)-01-28/2021-9921—बिहार लोक सेवा आयोग की 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सुश्री अनुराधा लक्ष्मी, संयुक्त मेधाक्रम-963 अनुक्रमांक-527665 की बिहार कारा सेवा (काराधीक्षक) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई।

2. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय ज्ञापांक-5506 दिनांक-09.07.2021 द्वारा सुश्री अनुराधा लक्ष्मी को दिनांक-16.07.2021 को शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु उपस्थित होने का निदेश दिया गया।

3. विभागीय पत्रांक-6817 दिनांक-06.08.2021 द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सुश्री अनुराधा लक्ष्मी के चरित्र एवं पूर्व वृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि इनके विरुद्ध संबंधित थानों में कोई शिकायत/काण्ड दर्ज नहीं है।

4. इसी क्रम में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित किया गया जिसके अनुसार सुश्री अनुराधा लक्ष्मी को बिहार प्रशासनिक सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित किया गया।

5. उपरोक्त कंडिका-04 के आलोक में विभागीय पत्रांक-10794 दिनांक-30.12.2021, 1100 दिनांक-07.02.2022 एवं 6854 दिनांक-22.06.2022 द्वारा सुश्री अनुराधा लक्ष्मी से बिहार कारा सेवा (काराधीक्षक) में योगदान हेतु उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन की माँग की गई।

6. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-6609 दिनांक-02.05.2022 द्वारा सुश्री अनुराधा लक्ष्मी की नियुक्ति बिहार प्रशासनिक सेवा में करते हुए परीक्ष्यमान वरीय उप समाहर्ता के पद पर सारण में पदस्थापित किया गया है। सुश्री अनुराधा लक्ष्मी द्वारा दिनांक-05.05.2022 को परीक्ष्यमान वरीय उप समाहर्ता का प्रभार भी ग्रहण कर लिया गया है। इनके द्वारा अभ्यावेदन दिनांक-05.09.2022 के माध्यम से सूचित किया गया कि वे काराधीक्षक के पद पर योगदान नहीं करना चाहती हैं।

7. अतः उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में एतद् द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार कारा सेवा (काराधीक्षक) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित सुश्री अनुराधा लक्ष्मी, संयुक्त मेधाक्रम-963 अनुक्रमांक-527665 की उम्मीदवारी (अभ्यर्थित्व) समाप्त की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।

**21 सितम्बर 2022**

सं0 कारा/स्था0(अधी0)-01-28/2021-9922—बिहार लोक सेवा आयोग की 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर श्री एस प्रतीक, संयुक्त मेधाक्रम-53 अनुक्रमांक-441403 की बिहार कारा सेवा (काराधीक्षक) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई।

2. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय ज्ञापांक-5505 दिनांक-09.07.2021 द्वारा श्री एस प्रतीक को दिनांक-16.07.2021 को शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु उपस्थित होने का निदेश दिया गया। परंतु वे उक्त तिथि को उपस्थित नहीं हुये। पुनः उन्हें दिनांक-19.07.2021 को जाँच हेतु उपस्थित होने का निदेश दिया गया जिसमें वे उपस्थित हुए।

3. विभागीय पत्रांक-6814 दिनांक-06.08.2021 द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, धनबाद (झारखंड) एवं विभागीय पत्रांक-6815 दिनांक-06.08.2021 द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण से श्री एस प्रतीक के चरित्र एवं पूर्व वृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि इनके विरुद्ध संबंधित थानों में कोई शिकायत/काण्ड दर्ज नहीं है।

4. इसी क्रम में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित किया गया जिसके अनुसार श्री एस प्रतीक को बिहार प्रशासनिक सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित किया गया।

5. उपरोक्त कंडिका-04 के आलोक में विभागीय पत्रांक-10794 दिनांक-30.12.2021, 209 दिनांक-12.01.2022, 6854 दिनांक-22.06.2022 एवं 7279 दिनांक-01.07.2022 द्वारा श्री प्रतीक से बिहार कारा सेवा (काराधीक्षक) में योगदान हेतु उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन की माँग की गई। श्री प्रतीक द्वारा सूचित किया गया कि बिहार प्रशासनिक सेवा में योगदान देने हेतु अब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है। इसलिए उनकी बिहार कारा सेवा (काराधीक्षक) के पद पर नियुक्ति संबंधी अभ्यर्थिता रद्द नहीं की जाय।

6. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-6609 दिनांक-02.05.2022 द्वारा श्री एस प्रतीक की नियुक्ति बिहार प्रशासनिक सेवा में करते हुए परीक्ष्यमान वरीय उप समाहर्ता के पद पर पठ्यम्पारण में पदस्थापित किया गया है। श्री प्रतीक द्वारा दिनांक-13.05.2022 को परीक्ष्यमान वरीय उप समाहर्ता का प्रभार भी ग्रहण कर लिया गया है।

7. अतः उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में एतद् द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार कारा सेवा (काराधीक्षक) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित श्री एस प्रतीक, संयुक्त मेधाक्रम-53 अनुक्रमांक-441403 की उम्मीदवारी (अभ्यर्थित्व) समाप्त की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

गृह विभाग  
(विशेष शाखा)

आदेश

21 सितम्बर 2022

सं०-एल/एच०जी०-14-07/2022-10853—महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4447, दिनांक-25.08.2022 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में श्रीमती प्रभा कुमारी, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, जहानाबाद को प्रथम संतान के लिए बिहार सेवा संहिता-220 एवं बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता-2014 के नियम (2) के तहत दिनांक-24.10.2022 से 21.04.2023 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस आदेश में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,  
अनिमेश पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं

26 जुलाई 2022

सं० 01/रा०स्था०(स्थानान्तरण)-36/2022 सह०-2541--श्री बिरेन्द्र शर्मा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर (अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, मुजफ्फरपुर) के चिकित्सा हेतु अवकाश पर चले जाने के कारण उनके अवकाश अवधि में श्री वात्सल्य मिश्र, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मुजफ्फरपुर पूर्व (अतिरिक्त प्रभार- सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मुजफ्फरपुर पश्चिम) को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, मुजफ्फरपुर का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार- राज्यपाल के आदेश से,  
सियाराम सिंह, उप-सचिव।

29 अगस्त 2022

सं० 01/रा०स्था०निजी- 68/2020 सह०-2891—श्री अभय झा, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग, वरीयता क्रमांक-32/18) सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में, की सेवा श्री अशोक चौधरी, माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आस सचिव के रूप में कार्य करने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सौंपी जाती है।

1. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार- राज्यपाल के आदेश से,  
सियाराम सिंह, उप-सचिव।

---

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

प्रभार प्रतिवेदन  
18 जुलाई 2022

सं० 8/नि०-1-102/2022-265—अधोहस्ताक्षरी मैं, निर्मल कुमार, बि०प्र०से० सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-14/पदा०-212/2012 - 11934, दिनांक-15.07.2022 के आलोक में आज दिनांक-18.07.2022 के पूर्वाह्न में संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना का स्वतः पदभार ग्रहण किया ।

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-14/पदा०-212/2012-11934, दिनांक 15.07.2022 द्रष्टव्य ।

निर्मल कुमार,  
भारग्राही पदाधिकारी ।

आदेश से,  
नित्यानन्द प्रसाद, संयुक्त सचिव (प्र०को०) ।

---

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय**  
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**  
**बिहार गजट, 28—571+10-डी०टी०पी०।**  
**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**

## भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

सूचना

सं० 1086—मैं सुनीता कुमारी, पति बालाजी, निवासी एन. ए./5, सिंचाई कॉलोनी, थाना पत्रकार नगर, कंकडबाग, पटना, शपथ पत्र सं. 3259 दिनांक 15.07.22 द्वारा घोषणा करती हूँ कि मेरा नाम सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में सुनीता कुमारी है, और विवाहोपरान्त मेरे बच्चों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में एवं मेरे वोटर कार्ड में सुनीता राय है। अतः मैं सुनीता राय के नाम से जानी जाऊँगी।

सुनीता कुमारी।

सं० 1089—मैं हुमा जेरीन थॉमस, माता श्रीमति एलिजाबेथ थॉमस, बंगाली टोला, समस्तीपुर, शपथ-पत्र संख्या 15791 दिनांक 25.08.2022 के आलोक में घोषणा करती हूँ कि, भविष्य में मैं हुमा खान की जगह हुमा जेरीन थॉमस नाम से ही जानी व पहचानी जाऊँगी।

हुमा जेरीन थॉमस।

No. 1090—I DEEPMALA D/o Surendra Prasad R/o D-4/2/IGIMS Sheikhpura, Patna-14 vide affidavit no. 13593 dated 13.09.2022 solemnly affirm that my name is Deepmala wife of Vibhuti Bhushan and Mother of Anushka Bhushan who is studying in D.P.S. Danapur, Patna (Bihar) in class 10<sup>th</sup> Sect.-H, Adm. No. 1495-11. My new name is Deepmala without any surname.

DEEPMALA.

No. 1101—I, RAGHWENDRA Kumar S/o Devendra Kumar Resident of Vill- Pura, P.O. Pura. P.S. Tekari, Dist. Gaya Bihar – 824236 here by declare by affidavit no. 11 dated 06.09.2022 shall be known as Raghawendra Kumar.

RAGHWENDRA Kumar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 28—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

# बिहार गजट

## का

## पूरक(अ0)

## प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० कारा/नि०को०(अधी०)—०१—२०/२०१९—९६४८

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय  
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

15 सितम्बर 2022

श्री रमेश प्रसाद, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, दाउदनगर के विरुद्ध उनके मंडल कारा, हाजीपुर में पदस्थापन के दौरान दिनांक 21.07.2019 को जिला प्रशासन, वैशाली द्वारा मंडल कारा, हाजीपुर में की गयी औचक छापेमारी में 08 मोबाईल फोन, 01 मेमोरी कार्ड, 5200 रुपया नकद राशि की बरामदगी के प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप पत्र के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1026 दिनांक 05.02.2020 द्वारा श्री रमेश प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमण्डल, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. विभागीय कार्यवाही के जांचोपरान्त संचालन पदाधिकारी-सह-संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमण्डल, पटना के पत्रांक 1065/स्था०, दिनांक 25.11.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप को अंशतः प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के प्रावधान के तहत विभागीय ज्ञापांक 646 दिनांक 25.01.2022 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए श्री रमेश प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

4. तद्आलोक में श्री रमेश प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के विश्लेषणोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7408 दिनांक 07.07.2022 द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(vi) के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया गया :-

“ संचयी प्रभाव से तीन (03) वेतनवृद्धियों पर रोक का दण्ड ”।

5. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7408 दिनांक 07.07.2022 द्वारा संसूचित उपर्युक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री रमेश प्रसाद द्वारा अपने पत्रांक 2309 दिनांक 11.08.2022 के माध्यम से पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि दिनांक 21.07.2019 को जिला प्रशासन की छापेमारी में उक्त अवधि में पदस्थापित प्रभारी मुख्य कार्यपालक कर्मी (प्रभारी उपाधीक्षक) को सिर्फ एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड विभाग द्वारा दिया गया है, जबकि उन्हें तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड दिया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। श्री प्रसाद का कहना है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने निष्कर्ष में उल्लेख किया गया है कि मंडल कारा हाजीपुर एन०एच० सहित तीन तरफ से रोड से घिरा हुआ है, जहाँ से असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार प्रतिबंधित सामग्रियों को कारा के अन्दर फेंका जाता रहा है। कारा की सुरक्षा एवं इस समस्या के स्थायी निदान हेतु कारा के पेरीमीटर वॉल के चारों तरफ सी०सी०टी०वी० कैमरा एवं जैमर लगाने के लिए आरोपी पदाधिकारी के द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से लगातार महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना से पत्राचार किया गया था। इसके अतिरिक्त मुख्य पेरीमीटर दीवाल की ऊँचाई बढ़ाने एवं उस पर Electrical Fencing कराने के लिए भी आरोपी पदाधिकारी द्वारा इस समस्या के निदान हेतु थानाध्यक्ष, हाजीपुर सदर, वैशाली तथा भवन प्रमण्डल, हाजीपुर से लगातार पत्राचार किया जाता रहा था। श्री प्रसाद का कहना है कि विभागीय कार्यवाही के सुनवाई के क्रम में गवाही देने हेतु उपस्थित गवाहों के द्वारा बयान दिया गया है कि मंडल कारा, हाजीपुर के तीन तरफ रोड है तथा



कारा के दीवाल के काफी नजदीक में निर्मित मकानों से बराबर असमाजिक तत्वों के द्वारा प्रतिबंधित सामान कारा के अन्दर फेंका जाता है। श्री प्रसाद का कहना है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा इसके बावजूद सिर्फ कार्यालय प्रधान होने के नाते आरोप को अंशतः प्रमाणित किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है।

श्री प्रसाद का अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कहना है कि वे लगातार कारा में तलाशी/छापेमारी कराते रहे, जब-जब आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुआ तो संबंधित पर F.I.R. भी दर्ज कराया। उन्होंने अपने पदस्थापन काल में 38 से ज्यादा F.I.R. दर्ज कराया है एवं अधीनस्थों पर भी कार्रवाई किया है। श्री प्रसाद द्वारा इस पुनर्विलोकन अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अधिरोपित दण्ड निरस्त/लघुकृत करने का अनुरोध किया गया है।

6. श्री रमेश प्रसाद के उपर्युक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि उन्होंने कारा में प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी के लिए कारा की भौगोलिक स्थिति एवं पेरिमीटर दीवाल की ऊँचाई कम होने तथा कारा में स्वीकृत क्षमता से कम सुरक्षा बल पदस्थापित होना बताया गया है। श्री प्रसाद का कहना है कि उन्होंने अपने पदस्थापन काल में प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी होने पर कई F.I.R. दर्ज किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि कारा में हमेशा आपत्तिजनक सामग्रियों की बरामदगी होती रहती थी, किन्तु श्री प्रसाद द्वारा अपने स्तर से कारा में इन प्रतिबंधित सामग्रियों के प्रवेश पर रोकथाम हेतु आवश्यक कारगर कदम नहीं उठाये गये। उनके द्वारा प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी के उपरान्त F.I.R. दर्ज किये जाने की कार्रवाई महज खानापूरी है। परिणामस्वरूप दिनांक 21.07.2019 को जिला प्रशासन की औचक छापेमारी में कारा के अंदर से 08 मोबाईल फोन सहित भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी हुई है। कारा के अन्दर से भारी संख्या में मोबाईल, नकद राशि एवं अन्य आपत्तिजनक/प्रतिबंधित सामग्रियों का बरामद होना श्री प्रसाद की अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता एवं पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही का द्योतक है।

श्री प्रसाद द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में पुनः उन्हीं बातों को दोहराया गया है, जिसका उल्लेख उन्होंने पूर्व में अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में किया था, जिसे सम्यक् विश्लेषणोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत करते हुए विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श प्राप्त कर विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुए श्री प्रसाद के विरुद्ध दण्ड अधिरोपित किया गया है।

7. उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री रमेश प्रसाद के विरुद्ध अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में बरती गयी घोर लापरवाही के आरोप प्रमाणित पाये गये हैं; फलस्वरूप विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त कर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री रमेश प्रसाद को “संचयी प्रभाव से तीन (03) वेतनवृद्धियों पर रोक का दण्ड” अधिरोपित किया गया है।

8. अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री रमेश प्रसाद, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, दाउदनगर के विरुद्ध गठित आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता पर विचार करने के उपरांत बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर समेकित रूप से उन्हें दिया गया दण्ड न्यायोचित है एवं इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इनके पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव—सह—निदेशक (प्र०)।

सं० कारा/नि०को०(अधी०)—०१—५०/२०१९—९६४९

### 15 सितम्बर 2022

श्री संजय कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर के विरुद्ध उनके मंडल कारा, मुंगेर में पदस्थापन के दौरान वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपूरक मो० हदीस नाज के द्वारा आपूरित सामग्रियों के विपत्र का भुगतान लंबित रखे जाने के आरोप के लिए गठित प्रपत्र ‘क’ के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8827 दिनांक 14.12.2020 द्वारा श्री संजय कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई, जिसमें आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी एवं अधीक्षक, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. विभागीय कार्यवाही के जांचोपरान्त संचालन पदाधिकारी—सह—आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा अपने पत्रांक 3756 दिनांक 16.10.2021 के माध्यम से विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री कुमार के विरुद्ध गठित प्रथम आरोप को अप्रमाणित तथा दूसरे आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के प्रावधान के तहत विभागीय ज्ञापांक 1670 दिनांक 21.02.2022 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए आरोपित पदाधिकारी श्री संजय कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

4. तदालोक में श्री संजय कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के विश्लेषणोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7328

दिनांक 04.07.2022 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(vi) के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया गया :-

“ संचयी प्रभाव से तीन (03) वेतनवृद्धियों पर रोक का दण्ड ”।

5. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7328 दिनांक 04.07.2022 द्वारा संसूचित उपर्युक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री संजय कुमार द्वारा अपने पत्रांक 4627 दिनांक 17.08.2022 के माध्यम से पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि वे दिनांक 29.06.2018 से 03.09.2018 तक की अल्प अवधि में मंडल कारा, मुंगेर में काराधीक्षक के पद पर पदस्थापित थे। वित्तीय वर्ष 2018-19 के सामग्रियों के भुगतान हेतु उनके उक्त अल्प अवधि के पदस्थापन के दौरान आपूरक मो0 हदीस नाज द्वारा कोई विपत्र भुगतान हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया था, जिसका उल्लेख प्रभारी उपाधीक्षक-सह-लेखा प्रभारी श्री श्रीमन् नारायण हिमांशु के द्वारा स्वयं कंटीजेन्ट पंजी में किया गया था। आपूरक मो0 हदीस नाज से उन्हें मंडल कारा, मुंगेर में अल्प अवधि में पदस्थापन के दौरान कोई मुलाकात/बात नहीं हुई थी। श्री संजय कुमार का अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कहना है कि कारा में सामानों की आपूर्ति हेतु संवेदकों का भी दायित्व होता है कि वे कार्यालय से विधिवत् प्राप्ति रशीद प्राप्त करें, परन्तु आपूरक द्वारा ऐसा नहीं कर सामानों की आपूर्ति नहीं करते हुए लगभग एक वर्ष के बाद अपने व्यावसायिक हित एवं दुर्भावनावश ऐसे आरोप लगाये गये हैं। श्री कुमार का कहना है कि संवेदक मो0 हदीस नाज द्वारा लगाये गये आरोप मनगढ़ंत, तथ्यहीन, असत्य एवं निराधार है।

6. श्री संजय कुमार के उपर्युक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि आपूरक मो0 हदीस नाज द्वारा आपूरित सामग्री का विपत्र श्री संजय कुमार, तत्कालीन अधीक्षक को प्रस्तुत किया गया था, जिसे कंटीजेन्ट रजिस्टर में अंकित करने के बाद काट दिया गया एवं आवेदक को उनके बकाये राशि का भुगतान जान-बूझकर नहीं किया गया। इस प्रकार श्री संजय कुमार द्वारा इस मामले में गंभीर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता बरती गई है। उनके द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों पर सारा दोषारोपण किया गया है, जो कार्यालय प्रधान के रूप में उनकी प्रशासनिक विफलता का परिचायक है। श्री कुमार द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में पुनः उन्हीं बातों को दोहराया गया है, जिसका उल्लेख उन्होंने पूर्व में अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में किया था, जिसे सम्यक् विश्लेषणोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत करते हुए विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श प्राप्त कर विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुए श्री कुमार के विरुद्ध दण्ड अधिरोपित किया गया है।

7. उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री संजय कुमार के विरुद्ध पदीय दायित्वों के निर्वहन में बरती गयी घोर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता के आरोप प्रमाणित पाये गये हैं; फलस्वरूप विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त कर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री संजय कुमार को “संचयी प्रभाव से तीन (03) वेतनवृद्धियों पर रोक का दण्ड” अधिरोपित किया गया है।

8. अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री संजय कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर के विरुद्ध गठित आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता पर विचार करने के उपरांत बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर समेकित रूप से उन्हें दिया गया दण्ड न्यायोचित है एवं इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इनके पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।

सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-50/2019-9650

### 15 सितम्बर 2022

श्री जलज कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी के विरुद्ध उनके मंडल कारा, मुंगेर में पदस्थापन के दौरान वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपूरक मो0 हदीस नाज के द्वारा आपूरित सामग्रियों के विपत्र का भुगतान लंबित रखे जाने के आरोप के लिए गठित प्रपत्र ‘क’ के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8826 दिनांक 14.12.2020 द्वारा श्री जलज कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई, जिसमें आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी एवं अधीक्षक, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. विभागीय कार्यवाही के जांचोपरान्त संचालन पदाधिकारी-सह-आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा अपने पत्रांक 2776 दिनांक 11.08.2021 के माध्यम से विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री कुमार के विरुद्ध गठित दोनों आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के प्रावधान के तहत विभागीय ज्ञापांक 8626 दिनांक 01.10.2021 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए आरोपित पदाधिकारी श्री जलज कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

4. तदालोक में श्री जलज कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के विश्लेषणोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7329

दिनांक 04.07.2022 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(vi) के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया गया :-

“ संचयी प्रभाव से तीन (03) वेतनवृद्धियों पर रोक का दण्ड ”।

5. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7329 दिनांक 04.07.2022 द्वारा संसूचित उपर्युक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री जलज कुमार द्वारा अपने पत्रांक 4067 दिनांक 30.07.2022 के माध्यम से पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि मंडल कारा, मुंगेर में अधीक्षक के पद पर पदस्थापन अवधि में आपूरक मो0 हदीस नाज के तथ्यहीन परिवाद, जो उनके मंडल कारा, मुंगेर में पदस्थापन से पूर्व का था, जिसमें आपूर्तिकर्ता मो0 हदीस नाज द्वारा त्रुटिरहित विपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् भुगतान कर दिये जाने के उपरांत भी उनको विभाग द्वारा तीन वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड निर्धारित किया गया है, जबकि उनके द्वारा आपूरक मो0 हदीस नाज के मंडल कारा, मुंगेर में आपूर्ति के विरुद्ध त्रुटिरहित विपत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार विपत्र को पारित किया जा चुका है। श्री जलज कुमार का कहना है कि उनके पदस्थापन के पूर्व ही आपूरक द्वारा सामानों की आपूर्ति की गयी थी, जिसका विपत्र भुगतान तात्कालिक अधीक्षक श्री संजय कुमार द्वारा नहीं किया गया था।

श्री जलज कुमार का कहना है कि आपूरक मो0 हदीस नाज का बकाया राशि रू0 4,24,310/- न हो कर मात्र रू0 4,07,338/- ही था। उनके द्वारा प्रस्तुत विपत्र की जाँच Gate register of Article & Stock register से किया गया, तो पाया गया कि मात्र रू0 4,07,338/-का ही भुगतान बकाया है, जिसे ठीक करने के लिए मो0 हदीस नाज को बुलाया भी गया। कई बार कक्षपाल एवं गृह रक्षकों को भी भेजा गया। जिस आपूरक को प्रतिदिन कारा पर आना है, वह बुलाने पर भी नहीं आया, उल्टे फर्जी विपत्र भुगतान का दबाव बनाते गया। यही वजह थी कि आपूरक मो0 हदीस नाज के भुगतान में विलम्ब हुआ, पर भुगतान तो पूर्ण जाँच कर उतना ही किया गया रू0 4,07,338/-, जितना उसका देय था। आपूरक मो0 हदीस नाज द्वारा निबंधित डाक से विपत्र भेजा गया है, जिससे उसकी मंशा साफ झलकती है कि नवागन्तुक अधीक्षक पर दबाव बनाया जाय। श्री कुमार द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में दिये गये दण्ड पर पुनर्विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

6. श्री जलज कुमार के उपर्युक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि विभागीय द्विसदस्यीय जाँच दल द्वारा जाँच में पाया गया कि कारा में दिनांक-17.06.2019 को विपत्र प्राप्त हुआ था। श्री जलज कुमार का कहना है कि विपत्र त्रुटिपूर्ण था, जिसे निराकरण हेतु जाँच की तिथि तक आपूरक से कोई पत्राचार नहीं किया गया। विभागीय जाँच में जब बातें उजागर हो गईं तब दिनांक-25.10.2019 को उनके द्वारा आपूरक को बकाया राशि रू0 4,07,338/- का भुगतान किया गया। इससे स्पष्ट है कि श्री जलज कुमार द्वारा जान-बूझकर आपूरक के विपत्र को लंबित रखा गया।

श्री कुमार द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में पुनः उन्हीं बातों को दोहराया गया है, जिसका उल्लेख उन्होंने पूर्व में अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में किया था, जिसे सम्यक् विश्लेषणोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत करते हुए विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श प्राप्त कर विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुए दण्ड अधिरोपित किया गया है।

7. उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री जलज कुमार के विरुद्ध पदीय दायित्वों के निर्वहन में बरती गयी गंभीर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता के आरोप प्रमाणित पाये गये हैं; फलस्वरूप विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त कर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री जलज कुमार को “संचयी प्रभाव से तीन (03) वेतनवृद्धियों पर रोक का दण्ड” अधिरोपित किया गया है।

8. अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री जलज कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी के विरुद्ध गठित आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता पर विचार करने के उपरांत बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर समेकित रूप से उन्हें दिया गया दण्ड न्यायोचित है एवं इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इनके पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।

सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-15/2016--9878

21 सितम्बर 2022

श्री रामाधार सिंह, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, दरभंगा (सम्प्रति अन्य मामले में निलम्बित काराधीक्षक) के मंडल कारा, दरभंगा में उपाधीक्षक के पद पर पदस्थापन अवधि में बंदी सियाराम सहनी के द्वारा काँच की शीशी तोड़कर अपना गला रेतकर आत्महत्या कर लेने की घटना में बरती गई कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही के प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप पत्र के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2743 दिनांक 31.05.2017 द्वारा श्री रामाधार सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया को संचालन पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, मंडल कारा, नवादा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमण्डल, गया के पत्रांक-1172/विधि, दिनांक-08.06.2020 द्वारा संचालन पदाधिकारी-सह-आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री रामाधार सिंह के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के प्रावधान के तहत विभागीय ज्ञापांक 4093 दिनांक 23.06.2020 द्वारा श्री सिंह को उक्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गई। तद्आलोक में श्री सिंह द्वारा अपने पत्रांक 3239 दिनांक 30.09.2020 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। श्री सिंह द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के कतिपय न्यायनिर्णयों का हवाला देते हुए विभागीय कार्यवाही में किसी की गवाही नहीं कराये जाने का उल्लेख किया गया।

4. तदोपरान्त संचालन पदाधिकारी-सह-आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया द्वारा समर्पित उक्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपित पदाधिकारी के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-18(1) के तहत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा गवाहों की गवाही नहीं करायी गई है। अतएव अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा यह मामला संचालन पदाधिकारी-सह-आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया को वापस करते हुए पुनः अग्रेतर जाँच एवं गवाही कराये जाने तथा गवाही के उपरान्त पुनः जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया।

5. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय पत्रांक-2235 दिनांक-08.03.2021 द्वारा संचालन पदाधिकारी-सह-आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया से उक्त विभागीय कार्यवाही में अग्रेतर जाँच एवं गवाही कराये जाने का अनुरोध किया गया।

6. तद्आलोक में आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमण्डल, गया के पत्रांक 3654/विधि, दिनांक 22.11.2021 के माध्यम से संचालन पदाधिकारी-सह-आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोपित पदाधिकारी श्री रामाधार सिंह के विरुद्ध गठित आरोप को अंशतः प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

7. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के प्रावधान के तहत विभागीय ज्ञापांक 1550 दिनांक 18.02.2022 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए आरोपित पदाधिकारी श्री रामाधार सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा/लिखित अभ्यावेदन की मांग की गई।

8. तद्आलोक में श्री रामाधार सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के विश्लेषणोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7330 दिनांक 04.07.2022 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(vi) के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया गया :-

**“ संचयी प्रभाव से दो (02) वेतनवृद्धियों पर रोक का दण्ड ”।**

9. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7330 दिनांक 04.07.2022 द्वारा संसूचित उपर्युक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री रामाधार सिंह द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन दिनांक 16.08.2022 समर्पित किया गया, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि उनके द्वारा पहली बार द्वितीय कारण पृच्छा में दिये गये जवाब के आलोक में विभाग द्वारा संचालन पदाधिकारी-सह-आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया को अग्रेतर जाँच एवं गवाही के उपरांत पुनः जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश विभागीय पत्रांक 2235 दिनांक 08.03.2021 द्वारा दिया गया, जिसके आलोक में आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया के पत्रांक-3654 दिनांक-22.11.2021 के द्वारा पुनः जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें उनके विरुद्ध गठित आरोप को अंशतः प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। श्री सिंह का कहना है कि उनके द्वारा जवाब में उठाये गये तथ्यों पर कोई विचार नहीं करते हुए उनके विरुद्ध कठोर दण्ड अधिरोपित कर दिया गया है। पाँच गवाहों में से मात्र दो गवाह (1) मो0 परवेज आलम, तत्कालीन कारा लिपिक, तथा (2) कक्षपाल श्री उमाशंकर राम की ही गवाही हुई है। तत्कालीन प्रभारी कारा अधीक्षक सहित तीन गवाह उपस्थित नहीं हुए। इन गवाहों द्वारा भी उनके विरुद्ध कोई बयान नहीं दिया गया। फिर भी संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध गठित आरोप को अंशतः प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है, जो न्यायसंगत नहीं है।

श्री सिंह का कहना है कि उन्होंने अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में भी इन बातों का जिक्र किया था, परन्तु अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उनके जवाब को अनसूना करते हुए स्वीकार करने योग्य नहीं माना गया। श्री सिंह द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उनके विरुद्ध अधिरोपित दण्ड पर पुनर्विलोकन कर आरोप मुक्त करने/अधिरोपित दण्ड को लघुकृत करने का अनुरोध किया गया है।

10. श्री रामाधार सिंह के उपर्युक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा उपस्थित हुए गवाहों से गवाही कराई गई है। संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच में श्री सिंह के विरुद्ध कैदियों को पर्याप्त सुरक्षा देने में लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता के आरोप प्रमाणित पाये गए हैं। न्यायिक जाँच प्रतिवेदन (MER) में एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा इस घटना के लिए जेल प्रशासन की लापरवाही बतायी गई है। बंदी सियाराम सहनी के द्वारा कारा में आत्महत्या किया जाना कारा में व्याप्त कुव्यवस्था को परिलक्षित करता है। इस घटना के समय श्री सिंह मंडल कारा, दरभंगा में उपाधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-799 एवं 800 के विहित प्रावधानों के तहत बंदियों की सुरक्षा एवं अभिरक्षा की जिम्मेवारी उपाधीक्षक के रूप में कारा के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होने के नाते आरोपित पदाधिकारी की थी, जिसके निर्वहन में वे पूर्णतः विफल रहे हैं। परिणामस्वरूप कारा जैसी अतिसुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्र में

एक अन्य बंदी द्वारा मृतक बंदी को प्रताड़ित किये जाने के कारण मृतक बंदी द्वारा आत्महत्या कर लिया जाना, श्री सिंह की अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता एवं पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही का द्योतक है।

11. श्री सिंह द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में पुनः उन्हीं बातों को दोहराया गया है, जिसका उल्लेख उन्होंने पूर्व में अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में किया था, जिसे सम्यक् विश्लेषणोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत करते हुए विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श प्राप्त कर विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुए श्री सिंह के विरुद्ध दण्ड अधिरोपित किया गया है।

12. उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री रामाधार सिंह के विरुद्ध अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में बरती गयी घोर लापरवाही के आरोप प्रमाणित पाये गये हैं; फलस्वरूप विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त कर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री रामाधार सिंह को "संचयी प्रभाव से दो (02) वेतनवृद्धियों पर रोक का दण्ड" अधिरोपित किया गया है।

13. अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री रामाधार सिंह, तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, दरभंगा (सम्प्रति एक अन्य मामले में निलंबित काराधीक्षक) संलग्न केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ के विरुद्ध गठित आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता पर विचार करने के उपरांत बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर समेकित रूप से उन्हें दिया गया दण्ड न्यायोचित है एवं इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इनके पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव—सह—निदेशक (प्र०)।

सं० ग्रा०वि०-R-503/90/2022-Section-14-RDD-RDD—1186446

### ग्रामीण विकास विभाग

#### संकल्प

29 अगस्त 2022

श्रीमती आशा कुमारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज (सुपौल) के विरुद्ध गुडिया पंचायत के पूर्व मुखिया पति- श्री शिवनारायण यादव से अवैध धन की उगाही करने संबंधी विडियो इलेक्ट्रॉनिक मिडिया न्यूज-18 पर वायरल हुआ, जिससे जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार की छवि धूमिल करने, उक्त कार्य से जीरो टॉलरेन्स नीति का उल्लंघन करने, वरीय पदाधिकारियों के आदेश/निदेश की अवहेलना करने तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली- 1976 के नियम-03 (1)(i)(ii) एवं (iii) के प्रतिकूल कार्य एवं आचरण करने का आरोप पत्र जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक- 351-2 दिनांक- 09.06.2022 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

प्राप्त आरोप पत्र पर विभागीय पत्रांक- 1032019 दिनांक- 27.06.2022 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जो सम्प्रति प्राप्त है। जिसमें श्री कुमारी के द्वारा उल्लेख किया गया है कि लेन-देन संबंधी आरोप निराधार है तथा वास स्थल क्रय सहायक योजना के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक- 26.03.2022 को 12 लाभुकों का मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायक योजना के तहत जमीन का निबंधन करवा दिया गया है।

श्रीमती आशा कुमारी के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोप एवं श्रीमती कुमारी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोप गंभीर प्रकृति एवं अवैध वित्तीय लेन-देन से संबंधित है, जिसकी वृहत् जांच की आवश्यकता है। श्रीमती आशा कुमारी के त्रिवेणीगंज प्रखंड में पदस्थापित रहने से जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप पत्र के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की संभावना है।

अतः श्रीमती आशा कुमारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(क) के तहत निलंबित करते हुये इनके विरुद्ध आरोप की वृहत् जांच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। निलंबन अवधि में श्रीमती आशा कुमारी का मुख्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्णियाँ निर्धारित किया जाता है।

निलम्बन की अवधि में श्रीमती आशा कुमारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

श्रीमती आशा कुमारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु श्री दिलीप कुमार अग्रवाल, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है एवं जिला पदाधिकारी, सुपौल को निदेश दिया जाता है कि जिला स्तर के किसी वरीय पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नामित करेंगे।

तदनुसार एतद् द्वारा श्रीमती आशा कुमारी को आदेश दिया जाता है कि संकल्प प्राप्त होने पर संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जैसा कि संचालन पदाधिकारी आदेश दें अपना स्पष्टीकरण/लिखित बचाव बयान (साक्ष्य सहित) उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
बालामुरुगन डी0, सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 28—571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>